भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3262

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक ऊर्जा संकट पर बहुपक्षीय प्रतिक्रिया

3262. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न हालिया ऊर्जा व्यवधानों के संदर्भ में बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक दक्षिण के देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा जी–20, ब्रिक्स, एससीओ और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) जैसे मंचों के माध्यम से की गई ताज़ा पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) होर्मुज जलडमरूमध्य से वैश्विक तेल और एलएनजी के प्रवाह में व्यवधानों के आलोक में, सरकार द्वारा ऊर्जा सुरक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा तथा जलवायु–अनुकूल विकास के मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच सहमति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान संकट से प्रभावित विकासशील देशों की सहायता के लिए रणनीतिक ऊर्जा भंडार, नवीकरणीय ऊर्जा भागीदारी और संकट–प्रतिक्रिया समन्वय के लिए किसी सामूहिक दक्षिण–दक्षिण सहयोग तंत्र की शुरुआत की है या इसका प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये पहलें वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को दर्शाने वाली अधिक समावेशी, प्रतिनिधि और लचीली बहुपक्षीय व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण को किसी प्रकार आगे बढ़ाती हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्गेरिटा)

(क) से (घ): भारत ने जी20, ब्रिक्स, एससीओ और 'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' जैसे मंचों के माध्यम से बहुपक्षवाद को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है, जिसमें वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हालिया व्यवधानों से उत्पन्न चिंताएं भी शामिल हैं। भारत विकासात्मक प्राथमिकताओं की रक्षा करते हुए, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य एवं उर्वरक सुरक्षा, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विकासशील देशों के बीच अधिक सहयोग का समर्थन करता है। भारत हालिया ऊर्जा व्यवधानों के संबंध में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से विचारों का आदान-प्रदान करने, सहमति बनाने और समन्वित दृष्टिकोण का समर्थन करने तथा साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से भागीदार देशों के साथ सहभागिता कर रहा है।

भारत ने "सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" के समग्र विषय के तहत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। सुदृढ़ता, अध्यक्षता के मुख्य स्तंभों में से एक है जिसके तहत ऊर्जा प्रणालियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और रूपरेखा की सुदृढ़ता पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। भारत विकासशील देशों की विकासात्मक प्राथमिकताओं और नीतिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, इस वर्ष जी20 में ऊर्जा आपूर्ति, ऊर्जा स्रोतों और प्रणालियों के विविधीकरण, ऊर्जा अवसंरचना में अधिक निवेश और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुदृढ़ता को बढ़ाने से संबंधित मामलों पर होने वाली चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन सहित, भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहलों में स्वच्छ ऊर्जा की सुविधा, ऊर्जा पहुंच, क्षमता निर्माण और स्थायी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा दिया गया है, जो दक्षिण-दक्षिण ऊर्जा सहयोग में योगदान देती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं और विकास प्राथमिकताओं को वैश्विक निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं के एजेंडे में रखा जाए। ये पहल अधिक समावेशी, प्रतिनिधिपूर्ण, न्यायसंगत और सुदृढ़ बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए भारत के निरंतर समर्थन में योगदान देती हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का शामिल होना और ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार, वैश्विक निर्णय निर्माण में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने के संबंध में भारत के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

*****